भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1887

उत्तर देने की तारीख 13 मार्च, 2023

सोमवार, 22 फाल्गुन, 1944 (शक)

भारत कौशल रिपोर्ट

1887 एडवोकेट ए.एम. आरिफ:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत कौशल रिपोर्ट में नवीनतम संस्करण के अनुसार देश में युवाओं की रोजगार-योग्यता वर्ष 2019 में 47.38 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022 में 46.2 प्रतिशत रह गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा धारकों में से केवल 21.43 प्रतिशत और आईटीआई प्रमाण-पत्र धारकों में से 31.3 प्रतिशत ही रोजगार योग्य हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से सहमत है कि कौशल विकास पर उसकी नीति छात्रों में आवश्यक कौशल सृजित नहीं कर पायी है; और

(घ) क्या सरकार का उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप और देश के युवाओं की रोजगार-योग्ता में वृद्धि करने के लिए मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों में सुधार करने का विचार है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख) व्हीबॉक्स द्वारा वर्ष 2022 को प्रकाशित भारत कौशल रिपोर्ट (आईएसआर) के अनुसार, देश में युवाओं की नियोजनीयता वर्ष 2019 में 47.38% से घटकर वर्ष 2022 में 46.2% हो गई और इसके अलावा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारक की नियोजनीयता 21.43% और आईटीआई प्रमाण-पत्र धारक 31.3% हैं। हालाँकि, वर्ष 2023 के लिए व्हीबॉक्स की नवीनतम भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष के 46.2% की तुलना में युवाओं की नियोजनीयता का आंकड़ा 50.3% है, जो एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसी तरह, वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों के लिए नियोजनीयता 27.61% और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाण-पत्र धारकों के लिए 34.2% है।

(ग) और (घ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), कुशल भारत मिशन के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत देश भर के युवाओं को कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह नियोजन विशेष रूप से पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के तहत ट्रैक किए जाते हैं। पीएमकेवीवाई के एसटीटी घटक के अंतर्गत, दिसंबर, 2022 तक कुल 68.02 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 54.26 लाख को प्रमाणित किया गया है और 23.39 लाख लोगों को नियोजित किया गया है, जो प्रमाणित संख्या का लगभग 43% है।

जेएसएस: जेएसएस के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्तियों को लाभकारी आजीविका के लिए जोड़ना और स्व-रोजगार और दिहाड़ी रोजगार के माध्यम से उनकी पारिवारिक आय को पूरक बनाना है। लाभार्थियों को रोजगार/नियुक्ति प्रदान करना जेएसएस स्कीम का अधिदेश नहीं है। जहां तक जेएसएस स्कीम के लाभार्थियों के रोजगार का प्रश्न है, जेएसएस में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव के रूप में स्कीम की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया है कि स्व और दिहाड़ी रोजगार और निजी जॉब संभव हुई हैं। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि स्कीम की उपयोगिता इस तथ्य से और स्पष्ट होगी कि लाभार्थी प्रशिक्षुओं में से 77.05% ने व्यावसायिक बदलाव किए हैं।

आईटीआई: आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट (कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2018 में प्रकाशित) में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्ण में से 63.5% को रोजगार (वेतन + स्वयं, जिनमें से 6.7% स्व-नियोजित हैं) मिला है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, इस स्कीम के एसटीटी घटक के तहत प्रमाणित उम्मीदवारों को दिहाड़ी रोजगार/स्व-रोजगार/शिक्षुता की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। व्यापक प्रचार के लिए नियोजन से संबंधित कार्यकलापों की समय-सारणी जिला कौशल समितियों (डीएससी) को परिचालित की जाती है। प्रशिक्षण भागीदार उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए डीएससी/राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) के साथ समन्वय में काम करते हैं। इसके अलावा, कुशल भारत मिशन के तहत स्कीमें मांग आधारित हैं। इस मिशन के अंतर्गत उद्योग की जरूरतों के आधार पर नए पाठ्यक्रमों का परिवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और ड्रोन टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मेक्ट्रोनिक्स, सौर तकनीशियन, 3-डी प्रिंटिंग आदि में पाठ्यक्रम पहले ही शामिल किए जा चुके हैं।

****